*hNeed to provide adequate compensation and employment to persons displaced due to acquisition of their land forcoal mining in Jharkhand-Laid

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : जैसा कि हम सभी जानते हैं झारखंड राज्य पूरे भारत में एक अग्रणी कोयला खनन राज्य है । झारखंड में 119 चालू कोयला खदानें हैं और इन खदानों से सालाना 15.6 करोड़ टन कोयला उत्पादन होता है । केंद्र सरकार द्वारा निजी कोल ब्लॉक की नीलामी आवंटन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनियों तथा निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है जिसमें स्थानीय ग्रामीणों की जमीन का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हुआ है । झारखंड ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा विस्थापन का दंश झेला है । अगर विकास के लिए विस्थापन जरूरी है तो उससे ज्यादा जरूरी विस्थापित लोगों का पुनर्वास है । परंतु झारखंड में जिन लोगों की जमीन पर कोल माइंस और पावर प्रॉजेक्ट लगाने का काम किया गया है उन्हीं लोगों को न तो सही ढंग से मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही उनके रोजगार की व्यवस्था की गई है । मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि विस्थापित लोगों की मदद के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें ।